आकाशवाणी शिमला

03.10.2025 / प्रादेशिक समाचार / 19.45बजे

मुख्य समाचार''

- केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा–स्वास्थ्य क्षेत्र का विस्तार केन्द्र सरकार की प्राथमिकता–एम्स बिलासपुर ने तीन वर्ष के कार्यकाल में हासिल की कई उपलब्धियां।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक अधिकारियों को लम्बित विकास परियोजनाएं जल्द पूरा करने के दिए निर्देश।
- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने मनाली क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा–लोगों के पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाने की जरूरत पर दिया बल।
- केन्द्र सरकार ने प्रदेश में दो नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने को दी मंजूरी–शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने केन्द्र का जताया आभार।

और

- शिमला में राज्य स्तरीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव शुरू–लोग 7 अक्तूबर तक ले सकेंगे हिमाचली व्यंजनों का आनंद।

एम्स बिलासपुर

केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि बिलासपुर में एम्स के निर्माण से प्रदेश के लोगों को बड़ी राहत मिली है और इसका निर्माण तीन वर्षों के रिकार्ड समय में पूरा किया गया है। जगत प्रकाश नड्डा ने आज एम्स के तीसरे स्थापना दिवस के मौके पर बिलासपुर में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की।

डिस्पैच––केन्द्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि केन्द्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ कर रही है और अनेक स्थानों पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान खोले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एम्स बिलासपुर ने बहुत कम समय में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। नड्डा ने एम्स के स्थापना दिवस पर संस्थान के अधिकारियों व कर्मचारियों सहित प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश में इस समय 23 एम्स संचालित हैं और इनमें 13 एम्स उनके कार्यकाल में स्थापित किये गए हैं।

जेपी नड्डा ने बताया कि एम्स बिलासपुर में 7 सौ 50 बिस्तरों की क्षमता वाला रोगी वार्ड और 40 विभागों वाला बाह्य रोगी विभाग कार्यरत है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यहाँ सभी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं।

नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी एम्स के विद्यार्थियों के लिये फैकल्टी एक्पोजर कार्यक्रम शुरू किया है जिसके अंतर्गत ये विद्यार्थी 15–15 दिन के लिये एक से दूसरे एम्स का दौरा करेंगे।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के विस्तार के लिये कृतसंकल्प है और इसके लिये पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है।

इस मौके पर हिमाचल के स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, सांसद अनुराग ठाकुर और हर्ष महाजन सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।

रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार एम्स बिलासपुर।

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक अधिकारियों को लम्बित विकास परियोजनाएं प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज प्रशासनिक सचिवों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अब से मुख्य सचिव सभी विभागों की परियोजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों को राज्य सरकार विशेष प्राथमिकता दे रही है और लोगों के कल्याण के लिए सरकार वचनबद्ध है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष आपदा के दौरान हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट जल्द तैयार करने के राजस्व विभाग को निर्देश दिए ताकि ये रिपोर्ट शीघ्र केन्द्र सरकार को भेजी जा सके।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज मनाली क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने क्षतिग्रस्त हुए राष्ट्रीय राजमार्ग का जायजा भी लिया और ब्यास नदी द्वारा मार्ग बदलने से हुए व्यापक नुकसान पर चिंता जताई। राज्यपाल ने सोलंग गांव का दौरा कर लोगों की समस्याएं भी सुनीं। शिव प्रताप शुक्ल ने लोगों के पुनर्वास के लिए तत्काल कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया।

मुख्य सचिव

कार्यकारी मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को वित्तीय अनुशासन अपनाने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज मुख्यमंत्री के साथ पहली बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों को जन–जन तक पहुंचाना और सभी योजनाओं का प्रभावी ढंग से संचालन करना उनकी प्राथमिकता है।

केन्द्रीय विद्यालय

केन्द्र सरकार ने प्रदेश में दो नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दी है। ये विद्यालय शिमला जिले के कोटखाई और सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में खोले जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने बताया कि ये नए केन्द्रीय विद्यालय राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत प्री–प्राईमरी स्तर से शिक्षा प्रदान करेंगे। रोहित ठाकुर ने बताया कि प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में लगभग 80 शिक्षण व गैर शिक्षण कर्मचारियों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने राज्य सरकार की मांग व सिफारिशों को समर्थन प्रदान करने के लिए केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का आभार जताया है।

स्वाद महोत्सव

शिमला में आज से राज्य स्तरीय ग्रामीण स्वाद महोत्सव शुरू हुआ जो 7 अक्तूबर तक चलेगा। इसमें हिमाचली व्यंजनों और मोटे अनाज पर आधारित अनेक स्टॉल लगाए गए हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने इस महोत्सव का शुभारम्भ किया। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य हिमाचली पारम्परिक व्यंजनों को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना और मोटे अनाजों की पौष्टिकता के बारे में लोगों को जागरूक करना है।

राजेश धर्माणी

नगर व ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार चिट्टा कारोबार में संलिप्त लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आज घुमारवीं के सीर उत्सव में नशे के खिलाफ जन–जागरूकता का संदेश देने के लिए निकाली गई पदयात्रा का नेतृत्व किया। राजेश धर्माणी ने कहा कि नशीले पदार्थों में कई बड़े अंतर्राष्ट्रीय गिरोह संलिप्त है जो युवाओं को नशे के जाल में फंसा रहे हैं। राजेश धर्माणी ने सीर उत्सव के मौके पर घुमारवीं अस्पताल में लगाए गए चिकित्सा शिविर का भी शुभारम्भ किया।

पंचायत चुनाव

ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह ने कहा है कि प्रदेश में पंचायती राज चुनाव इस वर्ष दिसम्बर में समय पर होंगे और अगले कुछ दिनों में आरक्षण रोस्टर जारी कर दिया जाएगा। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव पार्टी सिम्बल पर नहीं होते हैं और कांग्रेस संगठन न होने का इन चुनावों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

मुझे उम्मीद हैं, हमारी पूरी तैयारियां हो चुकी है और उम्मीद करते हैं कि समय से ही 2025 दिसम्बर में ही चुनाव होते हैं तो उम्मीद करते हैं इस बारी भी समय से ही चुनाव होंगे। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव बिना सिंबल के होते हैं। सिंबल के ऊपर थोड़ी होता है की कॉंग्रेस या बीजेपी या अन्य पार्टी का कोई सिंबल मिलेगा। कोई भी व्यक्ति फ्री है चुनाव लड़ने के लिए। और कोई भी चुनाव है पंचायती राज चुनाव की बात करूँगा, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद करूँगा, विधान सभा की, लोग अलग अलग तरीके से वोट डालते हैं। पंचायती राज चुनाव में भी थ्री टायर सिस्टम हैं, प्रधान है, बीडीसी और जिला परिषद हैं, वो भी लोग अलग अलग तरीके से डालते हैं तो इसमें संगठन का होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।